

छावनियों का राज्य नगर पालिकाओं के साथ वलिय

प्रलिस के लिये:

छावनियों का राज्य नगर पालिकाओं, [राज्य नगर पालिकाओं](#), [ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी](#), [शहरी स्वशासन](#), छावनी अधिनियम, 1924 के साथ वलिय करना।

मेन्स के लिये:

छावनियों को राज्य नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ वलिय करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने देश की 10 छावनियों (58 में से) के नागरिक क्षेत्रों को गैर-अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्रों को संबंधित [राज्य नगर पालिकाओं \(स्थानीय निकायों\)](#) में वलिय कर दिया जाएगा।

- सरकार की योजना उक्त छावनियों के कुछ क्षेत्रों को बाहर करने और ऐसे क्षेत्रों को राज्य के स्थानीय निकायों में वलिय करने की है।

छावनियाँ क्या हैं?

- छावनियाँ मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के आवास और सहायक बुनियादी ढाँचे के लिये नामित क्षेत्र हैं।
 - फ्रॉन्सीसी शब्द "कैंटन" से उत्पन्न, जिसका अर्थ है "कोना" या "ज़ालि", छावनियों को ऐतिहासिक रूप से अस्थायी सैन्य छावनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
 - हालाँकि समय के साथ, वे अर्ध-स्थायी बस्तियों में विकसित हो गए हैं जो सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिये आवास, कार्यालय, स्कूल तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- भारत में छावनियों का इतिहास [ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी](#) के काल से मिला है। पहली छावनी वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद वर्ष 1765 में कलकत्ता के पास बैरकपुर में स्थापित की गई थी।
 - इन क्षेत्रों को शुरू में सैन्य टुकड़ियों को तैनात करने के लिये बनाया गया था, लेकिन नागरिक आबादी को शामिल करने के लिये इसका विस्तार किया गया है जो सेना को सहायता और रसद सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- भारत के छावनी अधिनियम, 1924 ने छावनियों के शासन और प्रशासन को औपचारिक रूप दिया, उनके प्रबंधन, विकास तथा वनियमन के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान किया।

भारत में छावनी प्रशासन के लिये तंत्र क्या है?

- छावनियाँ और उनकी संरचना:
 - क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर छावनियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- वर्ग I से वर्ग IV तक।
 - जबकि प्रथम श्रेणी छावनी में आठ नरिवाचति नागरिक और बोर्ड में आठ सरकारी अथवा सैन्य सदस्य होते हैं, वहीं चतुर्थ श्रेणी छावनी में दो नरिवाचति नागरिक एवं दो सरकारी अथवा सैन्य सदस्य होते हैं।
 - यह बोर्ड छावनी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिये ज़िम्मेदार है।
 - छावनी का सटेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है तथा रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य-सचिव होता है।
 - आधिकारिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिये बोर्ड में नरिवाचति एवं नामांकित अथवा पदेन सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है।
- प्रशासकीय नियंत्रण

- रक्षा मंत्रालय का एक अंतर-सेवा संगठन प्रत्यक्ष रूप से छावनी प्रशासन को नयितरति करता है।
- भारत के संविधान की संघ सूची (अनुसूची VII) की प्रवर्षिटा 3 के अनुसार, छावनियों का शहरी स्वशासन तथा उनमें आवास भारत की संघ सूची का वषिय है।
- देश में लगभग 62 छावनियाँ हैं जनिहें छावनी अधनियम, 1924 (छावनी अधनियम, 2006 द्वारा सफल) के तहत अधसिचति कया गया है।
- नगर पालकियाँ द्वारा शहरी शासन की प्रशासनिक संरचना एवं वनियमन:
 - केंद्रीय स्तर पर: 'शहरी स्थानीय सरकार' का वषिय नमिनलखिति तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है:
 - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय।
 - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय।
 - केंद्रशासति प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय।
 - राज्य स्तर पर:
 - संविधान के तहत शहरी प्रशासन राज्य सूची का हसिसा है। इस प्रकार ULB का प्रशासनिक ढाँचा और वनियमन राज्यों में भनि-भनि है।
 - संविधान (74वाँ संशोधन) अधनियम, 1992 स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में शहरी स्थानीय नकियाँ (ULB, नगर नगिर्मो सहति) की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - इसने राज्य सरकारों को इन नकियों से राजस्व एकत्र करने के लयि कुछ कार्य, अधिकार एवं शक्ति सौपने का अधिकार दिया और साथ ही उनके लयि समय-समय पर चुनाव अनविर्य कर दिया।

छावनियों के नगर पालकियाँ में वलिय की क्या आवश्यकता है?

- वभिनि प्रतबिंध:
 - छावनी कषेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने लंबे समय से वभिनि प्रतबिंधों से संबंधति मुद्दों की शकियात की है और कहा है कछावनी बोर्ड उन्हें हल करने में वफिल रहे हैं।
 - उदाहरण के लयि, गृह ऋण तक पहुँच और परसिर के भीतर मुक्त आवागमन।
- स्थानीय शासन और नागरिक सुवधिएँ:
 - नागरिक कषेत्रों को नगरपालिका प्रशासन में शामिल करने से बेहतर नागरिक सुवधिएँ और ढाँचागत विकास हो सकता है।
 - स्थानीय शासन के मामलों में नवासियों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है, जसिके परिणामस्वरूप शहरी नयोजन और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर होंगी।

छावनियों को नगर पालकियाँ में वलिय करने में क्या मुद्दे हैं?

- कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ:
 - एक छावनी शहर से एक वलिय कयि गए नगर पालिका में परविरतन से छावनी और नागरिक कषेत्रों के बीच सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज तथा वदियुत जैसी बुनयादी ढाँचा प्रणालियों को एकीकृत करने जैसी वभिनि कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ आ सकती हैं।
- मौजूदा नरिवाचन कषेत्रों का वरिोध:
 - नगर पार्षद और राजनीतिक प्रतनिधि नए वलिय वाले कषेत्रों के समर्थन के लयि अपने नरिवाचन कषेत्रों से धन आवंटति करने का वरिोध कर सकते हैं।
 - यह प्रतरीध शहर के भीतर असमानताओं को और बढ़ा सकता है तथा वलिय वाले कषेत्रों में सेवाओं एवं बुनयादी ढाँचे में सुधार-प्रयासों में बाधा डाल सकता है।
- बुनयादी ढाँचे की मांग:
 - ULB में छावनी कषेत्रों को अचानक शामिल करने से जल की आपूर्ति, सीवेज ससि्टम, परविहन नेटवर्क और स्वास्थ्य देखभाल सुवधियों जैसे मौजूदा बुनयादी ढाँचे पर दबाव पड़ सकता है।
 - ULB को वलिय कयि गए कषेत्रों की जरूरतों को पूरा करने की दशिया में बुनयादी ढाँचे के उन्नयन और वसितार के लयि संघर्ष करना पड़ सकता है, जसिसे सेवा में व्यवधान तथा जीवन यापन की स्थिति खराब हो सकती है।
- पर्यावरणीय चति:
 - वलिय वाले कषेत्रों में अनयितरति नरिमाण और व्यावसायीकरण, वषिष रूप से हलि स्टेशनों जैसे पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील कषेत्रों में, पर्यावरण एवं स्थानीय पारस्थितिकि तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
 - खराब वनियमति विकास से नरिवनीकरण, मृदा अपरदन, भू-स्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिसुभेद्यता बढ़ सकती है।
- सुरक्षा संबंधी वचार:
 - नागरिक कषेत्रों की सैन्य प्रतषिठानों से नकिटता, वषिष रूप से रक्षा सुवधियों के समीप अनधिकृत नरिमाण और अतकिरण के संबंध में, सुरक्षा चतियों को बढ़ाती है।
 - सैन्य कर्मियों और परसिंपत्तियों की सुरक्षा सुनश्चिति करने के लयि ULB को सेना द्वारा नरिधारति सुरक्षा दशिया-नरिदेशों तथा नयिर्मो का पालन करना चाहिये।

India's Urbanization

KEY CHALLENGES

Urbanization is creating new employment opportunities, but not everyone benefits

Risks from disasters and economic shocks are a major issue in Myanmar's cities especially for the urban poor

Inequality in cities is evident and can create social tension given the density

Several vulnerable groups in urban areas such as ethnic minorities, migrants, the urban poor, women, and the disabled are marginalized



The needs for sustainable infrastructure and spatial planning in urban areas are massive

Conditions in informal settlements are especially poor, these areas are in greatest need for water, sanitation, solid waste management and transport services



POLICY RECOMMENDATIONS

Implementation will be reliant on a strong commitment from the government to a bold reform agenda



Invest in sustainable urban infrastructure and urban upgrading



Build resilience to mitigate the impact of shocks on people's livelihoods and health



Facilitate access to legal documentation for migrants and specific subgroups, and targeted social programs for those particularly vulnerable to exclusion



Invest in capacity building and new financing for urban development



